

OECD रपिर्ट में भारतीय किसानों के कराधान पर प्रकाश

प्रलिस के लयि:

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD), बाज़ार समर्थन मूल्य (MPS)

मेन्स के लयि:

सरकारी खरीद और वतिरण, सरकारी नीतयिं एवं पहलों का प्रभाव

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यो?

[आर्थिक सहयोग और विकास संगठन \(OECD\)](#) की कृषि नीति निगरानी तथा मूल्यांकन, 2023 नामक एक नवीनतम रपिर्ट ने वर्ष 2022 में भारतीय किसानों के अंतरनिहिति कराधान पर अपना स्पष्टीकरण दिया है।

- एक रपिर्ट के मुताबकि वर्ष 2022 में भारतीय किसानों पर 169 अरब अमेरिकी डॉलर का टैक्स लगाया गया।

रपिर्ट के मुख्य बडि:

- भारत का नकारात्मक MPS प्रभुत्व:**
 - वर्ष 2022 में OECD रपिर्ट में विश्लेषण कयि गए 54 देशों के बीच भारत के नकारात्मक बाज़ार समर्थन मूल्य (MPS) का वैश्विक स्तर पर 80% से अधिक ऐसे करो के लयि योगदान था।
 - 54 देशों में किसानों के लयि कुल अंतरनिहिति कराधान लगभग 200 बलियन अमेरिकी डॉलर था। भारतीय किसानों पर लगाया गया अंतरनिहिति कराधान आश्चर्यजनक रूप से 169 बलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जसिसे भारत इस परदृश्य में एक अग्रणी राष्ट्र बन गया।

बाज़ार समर्थन मूल्य (MPS):

- इसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के बीच मूल्य अंतर उत्पन्न करने वाले नीतगित उपायों के कारण "उपभोक्ताओं एवं करदाताओं द्वारा कृषि उत्पादकों को सकल हस्तांतरण के वार्षिक मौद्रिक मूल्य" के रूप में परिभाषित कयि गया है।
- यह किसानों द्वारा अनुभव कयि गए लाभ या हानि का माप है जब घरेलू कीमतें वैश्विक कीमतों से भिन्न होती हैं।
- उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऑफसेट प्रयास:**
 - नकारात्मक MPS वाली कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने बाह्य बजट समर्थन के माध्यम से MPS की भरपाई की है।
 - हालाँकि, भारत के मामले में, परिवर्तनीय इनपुट उपयोग के लयि बड़ी सब्सिडी के रूप में किसानों को विभिन्न बजटीय हस्तांतरण, जैसे उर्वरक, वदियुत और सचिाई जल, [प्रधानमंत्री किसान सममान नधि \(पीएम-किसान\)](#) ने घरेलू वपिणन नयिमें और व्यापार नीति उपायों के मूल्य-दबाने के प्रभाव को कम नहीं कयि।
- भारतीय किसानों पर प्रभाव:**
 - जबकि बजटीय हस्तांतरण सकल कृषि प्राप्ति का 11% था तथा विभिन्न वस्तुओं के लयि नकारात्मक MPS 27.5% था।
 - इस वसिगति के परिणामस्वरूप किसानों को सकल कृषि प्राप्ति का 15% नकारात्मक शुद्ध समर्थन प्राप्त हुआ, जो उनके लयि एक चतिाजनक स्थिति है।
- वर्ष 2022 में नरियात नीतयिं:**
 - वर्ष 2022 में भारत ने मुख्य रूप से [यूक्रेन में युद्ध](#) और वर्ष 2022 [हीटवेव](#) की प्रतिक्रिया के रूप में कई वस्तुओं पर नरियात

प्रतर्बिध, शुलक और परमटि प्रसतुत कयि ।

- इन नीतयिों का उद्देश्य घरेलू कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकना था, लेकिन ऐसा करने से कसिनों की प्राप्ति में कमी आई है ।
 - इन नरियात नीतयिों से प्रभावति वस्तुओं में वभिन्न प्रकार के चावल, गेहूँ, चीनी, प्याज और संबंघति उत्पाद, जैसे- गेहूँ का आटा, शामिल हैं ।
 - नरियात प्रतर्बिधों ने एक आपूर्तकिरता के रूप में भारत की वशिवसनीयता को सीधे प्रभावति कयिा और नयून कृषिआय की चुनौती को बढ़ा दयिा ।
 - इन नीतयिों ने न केवल घरेलू बाज़ारों को बल्कि वैश्विक कृषिउत्पादक के रूप में देश की स्थितिको भी प्रभावति कयिा ।
- वैश्विक परपिरेकष्य:
 - OECD रपिर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कसित् 2020-2022 के दौरान 54 देशों में कृषिक्षेत्र को प्राप्ति उत्पादक समर्थन सालाना औसतन 851 बलियिन अमेरिकी डॉलर था, जो क कोवडि -19 महामारी, मुद्रास्फीतिके दबाव और यूकरेन युद्ध के नतीजों की प्रतर्किरिया के कारण पर्याप्त वृद्धिको प्रदरशति करता है ।
 - वरूपण की संभावना:
 - 54 देशों में से उत्पादकों को दयिे गए दो-तहिई सकारात्मक समर्थन ने व्यापार और उत्पादन के लयिे "संभावति रूप से सबसे अधिक वकृति" माने जाने वाले उपायों का रूप लयिा ।
 - इन रूपों में आउटपुट पर आधारति भुगतान तथा परविरतनीय इनपुट का अप्रतर्बिधति उपयोग शामिल है, जसिसे अकषमता और लकषति समर्थन की कमी हो सकती है ।
 - अंतरराष्ट्रीय असमानताएँ:
 - उभरती अर्थव्यवस्थाओं में संभावति रूप से अधिक वकृति नीतयिों व्याप्त थी, जसिसे वर्ष 2020-2022 के दौरान उत्पादकों को सकारात्मक समर्थन (सकल कृषिप्राप्तयिों का 10%) और अंतरनहिति कराधान (सकल कृषिप्राप्तयिों का 6%) उत्पन्न हुए ।
 - इसके वपिरीत OECD देशों में संभावति रूप से वकृति करने वाली नीतयिों का स्तर कम था, लेकिन वे उत्पादकों पर परोक्ष रूप से कर नहीं लगाते थे ।

कसिनों से संबंघति भारत की पहल

- प्रधानमंत्री कसिन सममान नधि (PM-KISAN)
- कसिन करेडिट कार्ड (KCC)
- उत्तर पूर्वी कषेत्र हेतु मशिन जैवकि मूल्य शंखला वकिस (MOVCDNER)
- सतत कृषिपर राष्ट्रीय मशिन
- परमपरागत कृषि वकिस योजना (PKVY)
- कृषि वानिकी पर उप-मशिन (SMAF)
- राष्ट्रीय कृषि वकिस योजना
- एग्री-टेक (AgriStack)
- डिजिटल कृषि मशिन

आर्थिक सहयोग एवं वकिस संगठन (OECD):

- परिचय:
 - OECD एक अंतरसरकारी आर्थिक संगठन है जसिकी स्थापना आर्थिक प्रगत और वशिव व्यापार को प्रोत्साहति करने के लयिे की गई है ।
 - अधिकांश OECD सदस्य राष्ट्र उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं जनिका मानव वकिस सूचकांक (HDI) बहुत उच्च है और उन्हें वकिसति देश माना जाता है ।
- नीव:
 - इसके मुख्यालय की स्थापना वर्ष 1961 में पेरिस, फ्रांस में की गई थी और इसमें कुल 38 सदस्य देश हैं ।
 - OECD में शामिल होने वाले सबसे हालयिा देश अप्रैल 2020 में कोलंबिया और मई 2021 में कोस्टा रिका थे ।
 - भारत इसका सदस्य नहीं है, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है ।
- OECD द्वारा रपिर्ट और सूचकांक:
 - सरकार एक नज़र में
 - बेहतर जीवन सूचकांक

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कनिहें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? (2020)

1. सभी फसलों के कृषिउत्पाद के लयिे नयूनतम समर्थन मूल्य नरिधारति करना
2. प्राथमिक कृषि साख समतयिों का कम्प्यूटरीकरण

3. सामाजिक पूंजी विकास
4. कृषकों को नःशुल्क बजिली की आपूर्ति
5. बैंकगि प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी
6. सरकारों द्वारा शीतागार सुवधियों को स्थापति करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 5
- (b) केवल 1, 3, और 4 और 5
- (c) केवल 2, 3 और 6
- (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: C

प्रश्न. 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) स्कीम को क्रियान्वति करने का/के क्या लाह है/हैं? (2017)

1. यह कृषि वस्तुओं के लिये सर्व-भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वयापार पोर्टल है ।
2. यह कृषकों के लिये राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणता के अनुरूप कीमत मलिती है ।

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

??????

प्रश्न. भारत में कृषि उत्पादों के परविहन एवं वपिणन में मुख्य बाधाएँ क्या हैं? (2020)